should give loans to women enterpreneurs at differential rates of interest as a part of the special scheme for economically weaker sections. Similarly, there should be a twentyfive per cent reserved quota of jobs for women under the Integrated Rural Development Projects and National Rural Employment Project schemes of the 20-point programme. In addition, there should be immediate legislation to ensure equal wages in all sectors that involve skill and not just manual labour.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Kamal Nath, economic independence has already been obtained by men. Men have already got economic independence.

(Interruptions)

SHRI KAMAL NATH : The women Members should take this up. Since the women Members have not taken this up, I am compelled to do so.

(iii) Providing adequate funds in Seventh Five Year Plan for development of desert areas of the Country.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित वक्तव्य सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं :

पहाड़ी एवं रेगिस्तानी क्षेत्र देश के सब से पिछड़े क्षेत्र हैं। केन्द्र सरकार का ध्यान पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की ओर गया है परन्तु केन्द्र सरकार ने रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास में जो अभिरुचि दिखानी चाहिए, नहीं दिखाई।

योजना मंत्री जी ने यह स्पष्ट किया था कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में मापदण्डों को यदि परिवर्तन किया गया तो स्थिति में डिस्टार्शन पैदा होगी और यह आश्वासन दिया था कि जब सातवीं पंचवर्षीय योजना बनेगी तब इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बनाया जा रहा है। अत: मैंने योजना मन्त्री, ग्रामीण विकास मन्त्री एवं प्रधान मन्त्री तक का भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया।

प्रधान मन्त्री जी ने भी प्लानिंग कमीशन का ध्यान आकर्षित किया कि वे रेगिस्तानी क्षेत्रों को अधिक राशि प्रदान करने पर गौर करें।

छठी पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जब कि उनका क्षेत्रफल 2 लाख 31 हजार वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या सन् 1971 की जनसंख्या के अनुसार करीब 4 करोड़ है, 560 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की थी जिस में 90 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान एवं 10 प्रतिशत लोन था जब कि उसके मुकाबले रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जब कि उसका क्षेत्रफल 2 लाख 36 हजार वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या करीब 2 करोड़ थी, 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था जिस में 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता एवं 50 प्रतिशत राज्यों का हिस्सा था।

अत: केन्द्रीय सरकार से पुरजोर आग्रह एवं निवेदन है कि उक्त विषमता को मिटाने के लिए केन्द्रीय सरकार पहाड़ी क्षेत्रों के समकक्ष मरु क्षेत्रों के विकास में सातवीं पंचवर्षीय योजना में सात सौ करोड़ रुपये का प्रावधान करे जिसमें 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत लोन हो।